IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
03 फरवरी 2024
द हिंदू
पेपर- III (अर्थव्यवस्था)

जनसंख्या संबंधी प्राथमिकताएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने अंतरिम बजट भाषण में एक दिलचस्प वक्तव्य देते हुए कहा कि "तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जनसांख्यिकीय बदलावों" से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार दशकीय जनगणना को स्थगित किए जाने की पृष्ठभूमि में इस कथन के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह 1881 के बाद पहली मर्तबा है जब किसी दशक में जनगणना नहीं कराया गया है। यह स्पष्ट है कि भारत अब सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन 2020 में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019-21) से यह पता चलता है कि भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) गिरकर 2 हो गई है। कुल मिलाकर, सिर्फ कुछ राज्यों - बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) और मणिपुर (2.17) - का टीएफआर 2.1 से ऊपर है। साफ है कि, 20वीं शताब्दी में देखी गई उच्च जनसंख्या वृद्धि पर काफी हद तक लगाम लगा दिया गया है - टीएफआर 1950 में 5.7 से गिरकर 2020 में 2 हो गया है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में यह आंकड़ा अलग-अलग है। दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1951 में 26 फीसदी से घटकर 2011 में 21 फीसदी हो गई है, जो मुख्य रूप से बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिणामों और शिक्षा की वजह से टीएफआर में तेजी से आई कमी का नतीजा है और यह स्थिति इन राज्यों में उच्च प्रवासन दर के बावजूद है। भले ही उल्लिखित सर्वेक्षण ठोस और जरुरी हैं, फिर भी वे व्यापक जनगणना का विकल्प नहीं हैं। जनगणना कराने में हो निरंतर देरी केंद्रीय गृह मंत्रालय की खराब स्थिति को दर्शाती है, जो भारतीय शासन के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बजाय अन्य प्राथमिकताओं से प्रेरित है।

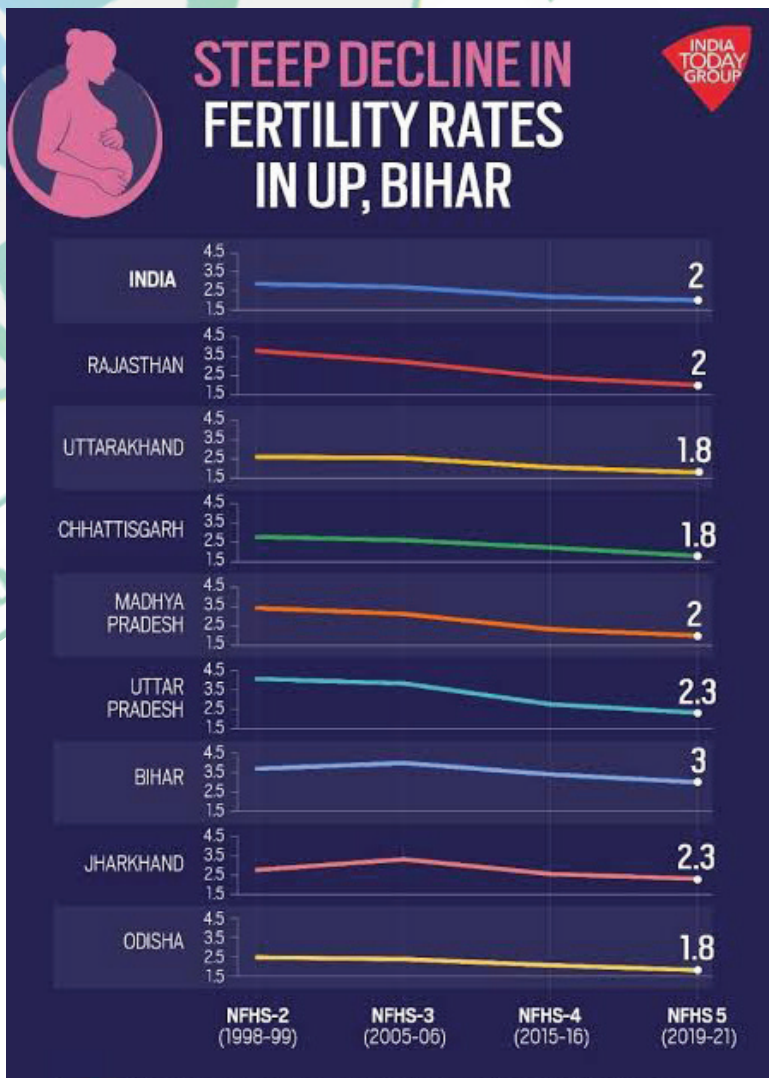

भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के चलते कई चुनौतियां और अवसर सामने आए हैं। बहुप्रचारित जनसांख्यिकीय लाभांश - विकासशील देशों में कामकाजी उम्र की आबादी का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात - सिर्फ तभी सार्थक है जब पर्याप्त नौकरियां हों और लोग कुछ हद तक उन सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठा पायें, जो उम्र बढ़ने पर उनके लिए मददगार साबित होंगी। उच्च बेरोजगारी और उत्पादकता में वृद्धि करने वाली व कुशल रोजगार

की जरूरतों को पूरा करने वाली गैर-कृषि नौकरियों के सृजन के पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत सुस्त होने की वजह से देश में इस लाभांश के जाया चले जाने की संभावना है। अगर यह "उच्चाधिकार प्राप्त" समिति नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सवालों तथा तेजी से हो रहे शहरी. करण व काम के मशीनीकरण के चलते नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का हल निकालने में सार्थक रूप से संलग्न होती है, तो वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर यह समिति जन. संख्या के मसले को धर्म और आप्रवासन के चश्मे से देखने की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पसंदीदा विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वह सिर्फ देश में तेजी से घटते लोकतांत्रिक लाभांश का सदुपयोग करने से शासन को भटकाएगी।

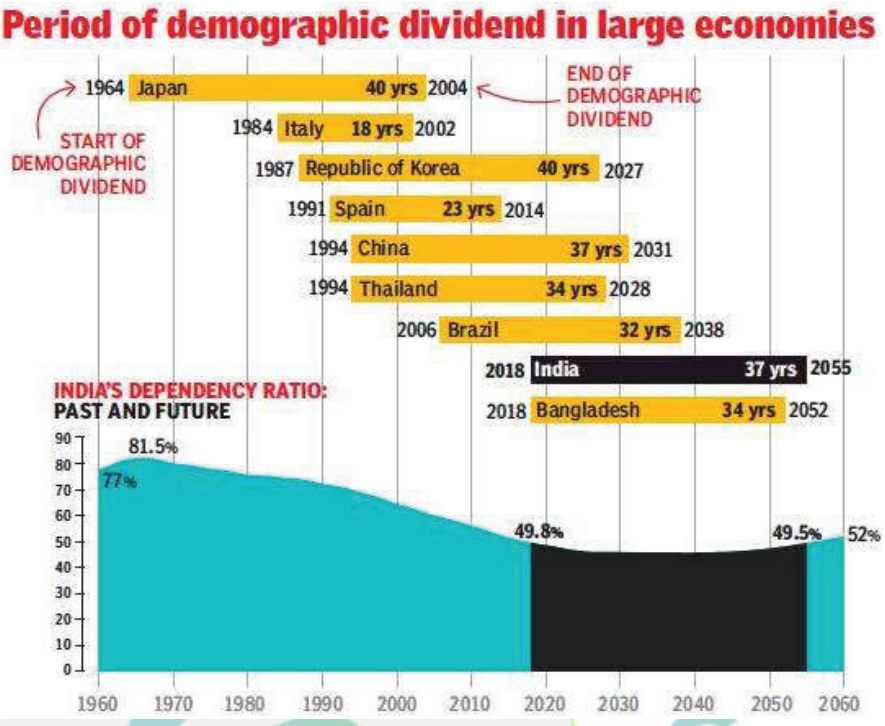

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत की जनसांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत के सभी राज्यों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 से कम हो गई है।
2. दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1951 की अपेक्षा 2011 में बढ़ी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the demography of India.

1. The total fertility rate (TFR) has fallen below 2.1 in all the states of India.
2. The share of population of the southern states has increased in 2011 as compared to 1951.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : D

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: हाल ही में भारत सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत सरकार के जनसांख्यिकीय मुद्दे पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के निर्णय की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इस निर्णय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की चर्चा करें साथ ही जनगणना की आवश्यकता की भी चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।